भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *314

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2023 को दिया जाना है।

.....

जलभराव की समस्या से निपटने के लिए मास्टर प्लान

***314. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन":**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बिहार के पटना जिले के मोकामा ताल क्षेत्र में जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि गंगा नदी में आठ अलग-अलग एजेंसियों द्वारा कार्य किया जा रहा है जिनमें से वेबकास्ट नामक एक एजेंसी को मास्टर प्लान तैयार करने का कार्य सौंपा गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का मोकामा ताल क्षेत्र में बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने के कार्य को प्राथमिकता देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो मोकामा ताल क्षेत्र बाढ़ के खतरों से कब तक मुक्त हो जाएगा और इसके सम्बन्ध में कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

“जलभराव की समस्या से निपटने के लिए मास्टर प्लान” के संबंध में दिनांक 20.07.2023 को लोक सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *314 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): इस मंत्रालय के अधीन गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) को गंगा बेसिन में बाढ़ प्रबंधन के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार करने और उसे आवधिक रूप से अद्यतन करने का अधिदेश प्रदान किया गया है। इन व्यापक मास्टर प्लानों को संबंधित राज्यों के साथ साझा किया जाता है ताकि उनमें की गई सिफारिशों के अनुसार, क्रियान्वित किए जाने हेतु विशिष्ट स्कीमें तैयार की जा सकें। जीएफसीसी ने किऊल-हरोहर उप-बेसिन सहित गंगा बेसिन में 23 नदी प्रणालियों के लिए व्यापक योजनाएं तैयार की हैं। मोकामा ताल क्षेत्र में जल जमाव की समस्या के समाधान से संबंधित सिफारिश को किऊल-हरोहर उप-बेसिन के लिए बनाए व्यापक मास्टर प्लान में शामिल किया गया है।

बिहार राज्य सरकार ने सूचित किया है कि गंगा बेसिन का मास्टर प्लान तैयार करने में उनके द्वारा किसी एजेंसी को शामिल नहीं किया गया है।

(ग) और घ): ताल क्षेत्र में जल प्रबंधन की समस्या का समाधान करने के लिए बिहार सरकार द्वारा दो प्रमुख परियोजनाएं शुरू की गई हैं। "मोकामा ताल क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी सुधार" परियोजना में 188.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ ताल क्षेत्र में गंगा और अन्य नदियों के बैकवाटर के प्रवेश को विनियमित करने के लिए, बाढ़ विरोधी स्लुइस-सह-नियामकों का निर्माण, पाइन्स की गाद निकालना और तटबंधों के नवीनीकरण का कार्य शामिल है। "ताल विकास योजना" नामक एक अन्य परियोजना में 1,178.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ पाइन्स से गाद निकालने, क्रॉसिंग/भूमिगत नाली, बैराज, चेक डैम/वीयर, हरोहर नदी के बाएं किनारे और ताल क्षेत्र की दक्षिणी सीमा पर तटबंध के निर्माण से संबंधित कार्य शामिल हैं। बिहार सरकार ने सूचित किया है कि इन कार्यों का उद्देश्य ताल क्षेत्र में जल के प्रवेश को नियंत्रित करना और जल निकासी में सुधार करना है।

*****